

एक नजर

द्वारिकाधीश जा रहे बस्ती के 3 लोगों की मौत



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुजरात-राजस्थान बॉर्डर पर गुजरात दर तल 2.30 बजे एक भीषण सड़क हादसे में बस्ती के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जोगीबारी गांव से एक परिवार कर से द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिसके बाद कार खाई में जा गिरी।

हादसे में कार चालक संतोष पांडे, सुभाषिता देवी और प्रमिला की मौत पर ही मौत हो गई। वहीं मिठाई लाल, अनीता, आशीष और कविता गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले सांचर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गुजरात के एक प्राइवेट अस्पताल में रेफर कर दिया। फिलहाल चारों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

गुजरात पुलिस ने हादसे की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। मृतकों में शामिल सुभाषिता देवी एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में सहायिका के पद पर कार्यरत थी, जबकि मिठाई लाल मजदूरी करते थे।

29 जून की सुबह 7 बजे परिवार द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए रवाना हुआ था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनके लिए इतनी भयानक साबित होगी। घटना की सूचना मिलते ही जोगीबारी गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं संख्या में ग्रामीण महिला परिवार के सहयोग के लिए घटनास्थल और अस्पताल पहुंचे हैं।

पुलिस ने तीन मृतकों के शवों का पोस्टमॉर्टम जांच के सांचर में करवाया और शव परिजनों को सौंप दिए हैं।

सरयू का जल स्तर बढ़ा



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। पहाड़ों से लेकर मैदान तक होना वाली बरसात के चलते सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है। एलियन ब्रिज और अयोध्या में जलस्तर की बढ़ोतरी जारी है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच गया है। बाढ़ खांड प्रधम के एसडीओ सहायक अधिकृत धर्मेष्ट सिंह ने बताया कि ऊपरी हिस्से में जलस्तर कम हो रहा है। इसका कारण अयोध्या में भी 24 घंटे बाद दिखने की संभावना है।

जलस्तर बढ़ने के साथ लोलपुर विक्रमजीत तटबंध और बीडी तटबंध 1 पर बाढ़ और कटान से निपटने के लिए तैयारी पूरी है। बंधे के रेटहोल और शाही होल की पूरी पैकिंग कर सर्विस रोड की समन्वित कार्य पूरा हो गया है। कन्हैपुर और सदनपुर में बन रहे डैमनरों का कार्य अंतिम चरण में पहुंच कर बाधित हो गया है, जिसे जलस्तर घटते ही पूरा करा लिया जाएगा। लोलपुर विक्रमजीत तटबंध के घोषीय में बनी बाढ़ चोकी पर जई अंतुल सिंह और जई आरके नायक की निगरानी ड्यूटी लगाई गई है। जलस्तर बढ़ने से घाटी तटबंध से सट गया है। ग्रामीणों का मानना है कि वार्निंग लेवल पार करने पर बाढ़ का पानी कल्याणपुर, मध्यापुर, चांदपुर और पड़ाम में घुसने लगता है। वहीं जलस्तर को लेकर गांववालों की भी चिंता है।

एक सीमा, तीन दुश्मन, चीन ने आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बनाया हथियारों की प्रयोगशाला



नई दिल्ली। (आभा)। भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ (केपीबिलिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी) लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान सामने आए रणनीतिक सबकों पर खुलकर चर्चा की। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन आधुनिक युद्ध की जटिलताओं को उजागर करने वाला एक अहम अनुभव रहा। उन्होंने कहा कि भारत को एक नई, बलिक तीन दुश्मनों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान, चीन और तुर्की का अप्रत्यक्ष समर्थन। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान चीनी हथियारों की प्रयोगशाला बना हुआ था।

लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने कहा, 'इस ऑपरेशन में हमारे सामने एक ही सीमा पर तीन दुश्मन थे। पाकिस्तान सामने था, लेकिन चीन ने उसे हर संभव मदद दी। पाकिस्तान के 81: सैन्य उपकरण अब चीनी हैं।' उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान को चीन की ओर से भारत के 'महत्वपूर्ण वेक्टरों' की लाइव जानकारी मिल रही थी, जिससे उनकी रणनीति को सीधा फायदा हुआ।

जनरल सिंह ने यह भी बताया कि तुर्की ने पाकिस्तान को टेलीजेंट पेशेवर अपराधी के विरुद्ध गैंगेस्टर में कार्रवाई करे प्रशासन- राजन चौधरी

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। विषय ज्ञान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन चौधरी ने मुख्य अधिकारी, जेडीपी के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देकर पेशेवर अभियुक्त सोनहार थाना क्षेत्र के परसाखुंड बुजुर्ग उर्फ वरिष्ठपुर जंगल निगरी शैलेश पुत्र हुदरगाम पर गैंगेस्टर की कार्रवाई करने की मांग किया है।

मेजे पत्र में राजन चौधरी ने कहा है कि शैलेश के विरुद्ध सोनहार के साथ ही जलपूर के अनेक थानों में गंभीर मामलों में मुकदमें दर्ज हैं। वह लगातार अपराध को अंजाम दे रहा है। यही नहीं उसने राजन चौधरी को जान से मार देने की नीयत से कई गांधी का पीछा किया और घर पर खड़ी गांधी नम्बर यूपी 61 ए.वी. 3132 कार को जला दिया। उसके अपराध पर पुलिस और प्रशासन चुपची साधे हुये हैं। मांग किया कि ऐसे शांतिर आगामी के विरुद्ध गैंगेस्टर की कार्यवाही की जाय।

आप सांसद संजय सिंह 8 को बस्ती में तैयारी बैठक में दायित्वों का वितरण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की बैठक जिलाध्यक्ष डा. राम सुभाष वर्मा ने बताया कि बैठक में सांसद संजय सिंह के स्वागत हुए अन्य कार्यकर्ता के लिये पदाधिकारियों में दायित्वों का वितरण किया गया।

बैठक में महिला जिलाध्यक्ष यश मिश्र, जिला महासचिव चन्द्रमणि वर्मा, संजय कुमार, चन्द्रमणि, वीरेंद्र यादव, तिलकराम मौर्य, राम अदालत गुप्ता, इन्द्रजीत कुमार, मोला राम यादव आदि उपस्थित रहे।

भोजन समेत कई तरह की आधुनिक ड्रोन तकनीक मुहैया कराई, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन से यह स्पष्ट हो गया कि भारत को एक और अधिक मजबूत व आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, इस बार हमारी आबादी वाले इलाकों को ज्यादा निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन अगली बार ऐसा हो सकता है। हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।

लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आतंकवादी ठिकानों

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के गांव अगौना में लगाया एक पेड़ मां के नाम



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शुक्रवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की कड़ी में महादेव विधानसभा क्षेत्र के अगौना में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की जन्मस्थली में पौधरोपण किया गया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के जिला संयोजक श्री अभिनव उषाया, महादेव विधानसभा के पूर्व विधायक रवि सोनहर ने पौधे लगाने के बाद कहा कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की जन्मस्थली हरा मरा रहे इसकी पहल सबको मिलकर करना होगा। कहा, कि यह एक सराहनीय पहल है जो हमारे वनस्पतियों और जीवों को बढ़ाएगी। जैसे-जैसे पेड़ बढ़ेंगे, हमारे पर्यावरण को

बेहतर बनाएंगे, हवा को शुद्ध करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण की तंत्र में योगदान देंगे। कहा कि एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से, हमारा परंपरागत और के बिना शर्त प्यार का सम्मान करते हुए हरित स्थान बनाया है। हम प्रत्येक नागरिक, ग्रामीणों से इस अच्छे काम में शामिल होने का आग्रह करते हैं। जिससे हरियाली बढ़े और प्रकृति से मुक्ति मिले।

कार्यक्रम में महादेव विधानसभा के संयोजक श्रुति अग्रहरि, कलवारी मंडल के संयोजक प्रेम प्रकाश, चौधरी सहित पदाधिकारी वंदु और कार्यकर्ता शामिल रहे।

आशा अधिकार मंच की बैठक में उठे मुद्दे



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। शुक्रवार को आशा अधिकार मंच की बैठक अमरेश शिव मंदिर के परिसर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सतिश पाण्डे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में आशा बहनों को मार्ग माह का मानदेय उपलब्ध कराये जाने, संसारी रोग मुक्ति अभियान में कार्य करने पर भुगतान दिये जाने

आदि मुद्दों पर विचार किया गया। जिलाध्यक्ष इस्मती चौधरी ने कहा कि यदि मांगें न मानी गईं तो संगठन आन्दोलन को बढ़ाए। बैठक में प्रदेश सचिव शारदा देवी, निर्मला तिवारी, संगीता देवी, ममता पाण्डेय, राजकुमार, पिंकी, सरोज वर्मा, सूर्यमोहि, प्रीती यादव, विन्दवासिनी आदि शामिल रही।

गई। परिजन डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर करीब निगम के अनुसार मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। दोषी पाए गए मुक्त के कार्रवाई की जाएगी। जाते के परिजन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं।

डा. एस. के. गौड़ के निजी अस्पताल को सौल करने में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने लम्बा वक़्त लगाया। अनेक संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था और आन्दोलन की चेतावनी भी दिया था।

यूपी में 2 नये निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी

लखनऊ (आभा)। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने दो नए निजी विश्वविद्यालयों के संचालन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति दे दी है। साथ ही गजियाबाद में अजय कुमार गार्ग विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आर्य पत्र जारी कर दिया है।

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार निजी शिक्षा की मांगदारी के जरिए उच्च शिक्षा में नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए दोनों विश्वविद्यालय प्रस्तावों को समर्थन प्रकिया के तहत मंजूरी दी गई है।

मंजूरी ने बताया कि अयोध्या में डीएम ने किया संचारी रोग अभियान का निरीक्षण

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। जिलाधिकारी रंजेश गुप्ता ने नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत नहरिया वार्ड में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आरम्भिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि नालियों में एंटीलार्वा छिड़काव व फागिंग का कार्य किया जा रहा है। वार्ड के समासद द्वारा अवगत कराया गया कि सुबह इस वार्ड की साफ-सफाई वेक की गयी है। वार्ड में सकाई कर्मचारी का स्टॉफ बहुत कम है, स्टॉफ बढ़ाने की आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देखा कि नालियों में नालियों में कहीं-कहीं साफ-सफाई

ठीक ढंग से नहीं है। उन्होंने अधिसूची अधिकारी को निर्देश दिया कि मोहल्ले के लोगों को भी जागरूक किया जाए कि साफ की हुई नाली में फिर से कचरा न डालें। इस जागरूकता हेतु समासद की सहभागिता भी ली। निरीक्षण के समय वार्ड के समासद, अधिसूची अधिकारी, नगर पालिका परिषद व संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

प्रशासन बताये आशा अधिकार मंच पंचायत है या नगर पंचायत में

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। सल्टोआ गोपालपुर-विकास खण्ड का आमा गांव न तो नगर पंचायत में है न ग्राम पंचायत में। इससे जहां विकास कार्य बाधित है वहीं नागरिक जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि बनाने के लिये परेशान हैं। अनेकों बार जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री के साथ ही सम्बंधित अधिकारियों को पत्र देने के बावजूद समस्या पूर्ववत् बनी हुई है। भागपुर तहसील क्षेत्र के आमा निवासी दीपेश विक्रम सिंह के पिता ओम प्रकाश सिंह का तब 3 दिसम्बर 2024 को निधन हो गया। तभी से उनके पुत्र और परिवार के लोग मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये दौड़ रहे हैं। मृत्यु प्रमाण-पत्र न बनने के कारण दीपेश विक्रम सिंह की माता को पेशन तक नहीं मिल पा रहा है। बैंक व तहसील में बरसत का काम बाधित है। इसी तरह से अनेक परिवारों के लोग परेशान हैं।

—जन्म- मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिये भटक रहे हैं लोग —उच्चाधिकारियों से लगाया न्याय की गुहार

लोग परेशान हैं। आमा निवासी दीपेश विक्रम सिंह ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी और सम्बंधित अधिकारियों से पत्राचार करते थक गये हैं किन्तु कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने

पुण्य तिथि पर चित्रांश क्लब ने स्वामी विवेकानन्द को किया नमन्:योगदान पर चर्चा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। चित्रांश क्लब द्वारा शुक्रवार को कर्मग्रीवाग के निकट तिष्ठत रमा टैंकिकल कॉलेज के परिसर में जिलाध्यक्ष प्रकाश मोहन श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानन्द की उम्मीत की 123 वी पुण्यतिथि पर याद किया गया।

क्लब संस्थापक राजेश चित्रांश, रत्नाकर श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, जी रहमान ने स्वामी विवेकानन्द के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये कहा कि स्वामी विवेकानन्द महज 39 साल जिए, पर इस दौरान हजारों वर्षों का काम कर गए। उन्होंने भारत को आध्यात्मिक रूप से जागृत किया। परेशानियों और मुसीबतों के पहाड़ के बीच उठकर जीवन बीता। अमावों में पैदा हुए और आजीवन इससे घिरे रहे। वे जब तक जीए भीमारियां से जुड़ते रहे। कहते हैं पूरे जीवन में उन्हें 31 तरह की प्रीतियां बड़ाईं। कहा कि अपने इसकी परवाह नहीं की। छोटी उम्र में अपने बालों वाले काम जबरन करते गए। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

क्लब अध्यक्ष प्रकाश मोहन ददल, फूल कुमार,नरेंद्र कुमार, मुखेश यादव, अयाज खान, जूही गुप्ता, नहारीसी से देश के अनेक हिस्से प्रभावित थे, उस समय युवा सन्यासी ने देश को उर्जा देने के साथ ही



—अयोध्या में खुलेगा महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय

महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 57 के तहत आर्य पत्र जारी किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संस्थान को कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इनमें न्यूनतम पांच करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि, शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ भूमि और कम से कम 24 हजार वर्ग मीटर का शैक्षणिक बुनियादी ढांचा शामिल है।

उन्होंने बताया कि इसी तरह भारतीय प्रबंधन एवं इंजीनियरिंग सोसायटी, गजियाबाद द्वारा प्रस्तावित

संचारी रोग अभियान का निरीक्षण



डीएम ने किया संचारी रोग अभियान का निरीक्षण

प्रशासन बताये आशा अधिकार मंच पंचायत है या नगर पंचायत में



—जन्म- मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिये भटक रहे हैं लोग —उच्चाधिकारियों से लगाया न्याय की गुहार

लोग परेशान हैं। आमा निवासी दीपेश विक्रम सिंह ने बताया कि वे मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी और सम्बंधित अधिकारियों से पत्राचार करते थक गये हैं किन्तु कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने

पुण्य तिथि पर चित्रांश क्लब ने स्वामी विवेकानन्द को किया नमन्:योगदान पर चर्चा

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। चित्रांश क्लब द्वारा शुक्रवार को कर्मग्रीवाग के निकट तिष्ठत रमा टैंकिकल कॉलेज के परिसर में जिलाध्यक्ष प्रकाश मोहन श्रीवास्तव के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी विवेकानन्द की उम्मीत की 123 वी पुण्यतिथि पर याद किया गया।

क्लब संस्थापक राजेश चित्रांश, रत्नाकर श्रीवास्तव, अजय कुमार श्रीवास्तव, जी रहमान ने स्वामी विवेकानन्द के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये कहा कि स्वामी विवेकानन्द महज 39 साल जिए, पर इस दौरान हजारों वर्षों का काम कर गए। उन्होंने भारत को आध्यात्मिक रूप से जागृत किया। परेशानियों और मुसीबतों के पहाड़ के बीच उठकर जीवन बीता। अमावों में पैदा हुए और आजीवन इससे घिरे रहे। वे जब तक जीए भीमारियां से जुड़ते रहे। कहते हैं पूरे जीवन में उन्हें 31 तरह की प्रीतियां बड़ाईं। कहा कि अपने इसकी परवाह नहीं की। छोटी उम्र में अपने बालों वाले काम जबरन करते गए। वे असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

क्लब अध्यक्ष प्रकाश मोहन ददल, फूल कुमार,नरेंद्र कुमार, मुखेश यादव, अयाज खान, जूही गुप्ता, नहारीसी से देश के अनेक हिस्से प्रभावित थे, उस समय युवा सन्यासी ने देश को उर्जा देने के साथ ही

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

भारतीय बस्ती

बस्ती 5 जुलाई 2025 शनिवार

सम्पादकीय

बीच बहस में मतदाता सूची

बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े किये हैं। सबसे मुश्किल यह है कि आधार और राशन कार्ड जैसे व्यापक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों को चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा है। जाहिर है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों, जैसे दलित, आदिवासी, और अल्पसंख्यकों, के माताधिकार पर असर पड़ सकता है। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए होने वाले चुनाव में सभी वैध मतदाताओं को मतदान का अधिकार होना चाहिए और नियम के मुताबिक अपात्र लोगों को मतदाता सूची से हटाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश के मायने समझे जा सकते हैं। सवाल है कि अगर इस सूची को दुरुस्त करने के क्रम में किसी मजदूरी या अन्य परिस्थितियों की वजह से वैसे लोग भी मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में इसके हकदार हैं, तो इसकी जवाबदेही किस पर होगी।

यह सही है कि समय-समय पर अलग-अलग वजहों से अपात्र हो चुके लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर नई परिस्थितियों में जिस तरह चुनाव आयोग ने सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत की है, उसमें इस बात की आशंका खड़ी हो गई है कि क्या इसमें बड़ी तादाद में वैसे लोग भी मतदान के लिए अपात्र करार दिए जाएंगे, जिनके पास आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज किन्हीं वजहों से उपलब्ध नहीं हैं। मतदाता सूची को त्रुटियों से रहित बनाने का काम निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन विपक्षी दलों की ओर से इसके औचित्य पर सवाल उठाने के भी अपने आधार हैं। आयोग की ओर से इस सूची में बने रहने के लिए जिन स्वीकार्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, बिहार के बहुत सारे लोगों को लिए यह एक बेवद मुश्किल काम होगा।

ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी-खासी होगी, जिनके पास खुद को सही साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे और अगर वे इन्हें नए सिरे से बनवाने के काम में लगेंगे तो इसके लिए समय की जरूरत होगी। जबकि बिहार में अक्तूबर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए महज एक माह का समय दिया गया है।

स्वाभाविक ही इस समय के चुनाव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, अगर उसमें शामिल होने के पात्र लोग किन्हीं वजहों से छूट गए, तो उनके दावों और आपत्तियों को निपटाने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? यह छिपा नहीं है कि बिहार में एक बड़ी आबादी ऐसे गरीब और कम शिक्षित लोगों की है, जिनके पास सरकारी ओर से जारी अधिकारिक दस्तावेज नहीं होंगे। खासतौर पर जन्म पंजीकरण के मामले में काफी पीछे रहने की वजह से बहुत कम लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र हैं। हालांकि हाशिये के समुदायों के ज्यादातर लोगों की पहुँच आधार और राशन कार्ड तक है, जिनकी मांग आमतौर पर हर चीज के लिए की जाती है। अगर यह सामान्य मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से इन्हें स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया है।

निर्वाचन आयोग की ओर से मले ही यह कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों को ताजा दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में लोग इस दायरे में आएंगे, उनके लिए भी निर्धारित दस्तावेज जमा करना आसान नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के मतदाता सूची से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है और विपक्षी दल इस कवायद को समान अवसर के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में आयोग के सामने सारे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि नए नियमों की वजह से किसी भी वैध मतदाता के मतदान का अधिकार का हनन न हो।

अखिलेश की बदलती राजनीति और हिन्दुत्व का दांव



—संजय सक्सेना—

2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव हर हाल में सत्ता में वापसी की जुगत में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा का आधार लंबे समय तक मुलामय सिंह यादव द्वारा स्थापित मुस्लिम-यादव (एम-वाई) समीकरण रहा है। इस समीकरण के सहारे मुलामय सिंह तीन बार और अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। लेकिन 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए बदलाव ने सपा के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने हिंदुत्व की छतरी तले विभिन्न हिंदू जातियों को एकजुट करने में सफलता हासिल की है, जिसने सपा की परंपरागत रणनीति को कमजोर कर दिया है। अखिलेश यादव अब इस बदले सियासी परिदृश्य में अपनी पार्टी की छवि को नया रूप देने और व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीछीए (फिफ्थ डिविजन, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस रणनीति ने सपा को कुछ हद तक सफलता दिलाई, लेकिन बीजेपी ने इसके बाद फिर से सपा के खिलाफ सियासी तात्बाबाना बुना शुरू कर दिया है। ऐसे में अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए सनातन धर्म के प्रतीकों को अपनाते



उत्तर प्रदेश में सपा की राजनीति का आधार लंबे समय तक मुस्लिम और यादव वॉटर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने सपा पर यादववाद और मुस्लिम तुष्टिकरण की छवि गढ़ने में सफलता हासिल की है, जिससे सपा का वोट आधार सीमित होता गया। अखिलेश यादव को इस बात का अहसास हो चुका है कि केवल एम-वाई समीकरण के सहारे बीजेपी को हराना अब संभव नहीं है। यही वजह है कि वे अपनी पार्टी की छवि को बदलने और व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीछीए (फिफ्थ डिविजन, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। इस रणनीति ने सपा को कुछ हद तक सफलता दिलाई, लेकिन बीजेपी ने इसके बाद फिर से सपा के खिलाफ सियासी तात्बाबाना बुना शुरू कर दिया है। ऐसे में अखिलेश अब सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए सनातन धर्म के प्रतीकों को अपनाते

की कोशिश कर रहे हैं। सावन का महिना, जो 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से उत्तर भारत में खास महत्व रखता है। इस दौरान लाखों भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर यादव बंधू गौरी केन्दारेश्वर, तिलगांडेखर, और फिर दशाश्वमेय घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। इसके बाद मृत्युंजय महादेव, त्रिलोचन महादेव और काल भैरव के दर्शन कर यह यात्रा पूरी होती है। इस बार अखिलेश यादव के इस आयोजन में शामिल होने को सियासी हलकों में व्यापक रूप से चर्चा का विषय माना जा रहा है। यह कदम न केवल उनकी धार्मिक आस्था को दर्शाता है, बल्कि सपा की छवि को मुस्लिम परस्ती से बाहर निकालने और सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी है।

अखिलेश यादव की यह रणनीति उनकी पार्टी को मुलामय सिंह यादव के दौर की छवि से बाहर निकालने की कोशिश का हिस्सा है। मुलामय सिंह ने सपा की नींव मुस्लिम और यादव वोटों के आधार पर रखी थी, लेकिन बदले सियासी हालात में यह समीकरण अब पर्याप्त नहीं है। बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को केंद्र में रखकर विभिन्न हिंदू जातियों को एकजुट करने में सफलता हासिल की है। सपा पर लगातार यादववाद और मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोपों ने अखिलेश के लिए सत्ता में वापसी की राह को और मुश्किल बना दिया है। खासकर, ब्राह्मण और ठाकुर समुदायों के बीच सपा के प्रति नाराजगी बढ़ी है, क्योंकि अखिलेश के कुछ बयानों को इन समुदायों के खिलाफ माना गया है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में जलामिषिक का यह कदम सनातन धर्म को मानने वाले व्यापक समुदाय के बीच सपा की स्वीकार्यता बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2014 के बाद से देश की सियासत में हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ा है। बीजेपी ने हिंदू महादत्ताओं को एकजुट करने में सफलता हासिल की है, जिसने विपक्षी दलों की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव का काशी दौरा इसी बदलते सियासी परिदृश्य का हिस्सा है। वे न केवल अपने परंपरागत यादव वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि अन्य हिंदू समुदायों, खासकर सनातन धर्म को एकजुट देखने वालों का समर्थन भी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि, बीजेपी की पिछ पर उत्तरकाली मुखाबला करना सपा के लिए आसान

नहीं है। बीजेपी ने हिंदू समुदाय को अपना मजबूत वोट बैंक बना लिया है, और सपा का सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव कितना कारगर होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के एजेंडे को भी मजबूत करने की कोशिश में हैं। मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर मुखर होने के बजाय, वे अब सामाजिक समावेशिता और पीछीए फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं। काशी में जलामिषिक का यह कदम न केवल धार्मिक, बल्कि सियासी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह सपा को बीजेपी के हिंदुत्व के नैरेटिव का जवाब देने और व्यापक हिंदू समुदाय के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का मौका देता है। हालांकि, इस रणनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अखिलेश यादव कितनी कुशलता से अपनी पार्टी की पुरानी छवि को बदल पाते हैं और बीजेपी के सियासी ताने-बाने का जवाब दे पाते हैं। कुल मिलाकर, अखिलेश यादव का सावन के पहले सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर में जलामिषिक करना एक सोच-समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है। यह कदम उनकी बदलती राजनीति को दर्शाता है, जहां वे परंपरागत एम-वाई समीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के प्रतीकों को अपनाते और व्यापक सामाजिक समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में नए रूप भरने की कोशिश में जुटे हैं।

स्त्री हो या पुरुष : अपराध अक्षम्य है

—क्षमा शर्मा—

राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरह मरेले में मुसकान ने अपने पिता को मारकर नीले ड्रम में बंद कर दिया था और पुरुष मित्र के साथ घूमने घली गई थी, सोनम तो अपने पिता राजा के साथ ही गई थी। हां, पहले से वहां थे तीन लड़के मौजूद थे, जो कथित हत्यारे बताए जा रहे हैं। जिस तरह मुसकान के परिवार वालों ने अगर कहा कि अगर उसने ऐसा किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, सोनम का भाई भी इसी तरह के बयान दे रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि इस तरह के बयान पुलिस से बचने के लिए दिए जाते हैं। खैर, जो भी हो एक निष्कर्ष निकलने में जान गंवाई है। कल इन अपराधियों को सजा मिले भी जाए, तो राजा के माता-पिता जीवन भर इस दुःख को लेकर जीएंगे। कई लोगों ने अखबारों और सोशल मीडिया में लिखा कि लड़कियां ऐसा इसलिए कर रही हैं कि माता-पिता उनकी सुनने नहीं हैं। वे बिना उनकी मर्जी के शादी कर देते हैं। अगर वे उनकी सुन लें, तो ऐसा न हो। जबकि मुसकान ने तो अपनी मर्जी से ही शादी की थी।

इन दिनों ऐसे किस्से आम हैं जब पिता ने पत्नी या महिला मित्र अलग पत्नी ने पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि उसे किसी ओर के साथ रहना था। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सोनम द्वारा पुरुषों कांड के बाद, लोग शादी के बाद घूमने जाने से बच रहे हैं। टिकट घूंसना सख्त कर रहे हैं। यही नहीं विवाह से पूर्व प्राइवेट जासूसों की मदद से होने वाले सखी का बेक ग्राउंड चेक करना है। यहां तक कि कथित विज्ञान पर दिए जा रहे हैं। एक ऐसा ही विज्ञान फेंसबुक पर देखा। यह एक अखबार में छपाया गया था। इसमें लिखा था— मुसकान तोषा को अगर लड़की से सगाई हो सारी। किसी को आपत्ति हो तो बता। ऐसी बातों से कई बार उन स्त्रीमेलेस की पी बारह हो सकती है, जो किसी लड़की को या लड़के को परेशान करने के लिए तरह-तरह की जुगत भिड़ाने हैं। मान लीजिए बेवजह ही कोई आकर कह दे कि हां तो इस शादी से मुझे आपत्ति है, क्योंकि इस लड़के या इस लड़की से मेरे सन्धे है। ऐसे में अगर शादी हो भी जाए, तो शांका का एक बीज हमेशा के लिए बोया जा सकता है। आपसी रिश्तों में इतना अविश्वास, फिर शादी, विवाह, किसी रिश्ते में



बहुत से विद्वान और विदुषियां कह रही हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि महिलाओं को सदैयों से दबाकर रखा गया है। अब वे ताकतवर हुई हैं, तो ऐसा कर रही हैं। आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं कि महिलाएं तो बस छह प्रतिशत अपराध ही करती हैं। बहुसंख्य अपराध तो पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं।

जाने की जरूरत ही क्या है। जब आपस में विचारसंगम न रहा तो क्या ही रहे। एक बात बार-बार कही जा रही है कि लड़कियां मला अपराधी कैसे हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकतीं। लड़कियों की वह बेचारी और बुद्धि युक्त कुप न जानने वाली की छवि तब तक दोती रहेगी। लड़कियां या लड़के, अपराधी कोई भी हो सकता है।

असम न्याय फाउंडेशन की दीपिका फाउंडेशन कहते हैं कि अपराध पति-पत्नी के रिश्तों में घरेलू हिंसा और क्रूरता को रखा जाना है, लेकिन अब रक्त आम हो गया है, जब यह भी देखा जा रहा है कि ऐसे रिश्तों में हत्या जैसे जघन्य अपराध कितने हो रहे हैं। दीपिका के एक अध्ययन में पाया कि 2023 में 306 अपराधों को उनकी पत्नियों ने मार दिया। इन घटनाओं को आमलेख्य बनाने की कोशिश की गई। वर्ष 2025 से इन छह महिनों में यह संख्या तो से अधिक पहुंच गई है। दीपिका ने शादी के वहीद (मैरिज एंड मैरिज) और भारत के बेटे (इंडियन सेंस) नामक दो फ़िल्में भी बनाई हैं।

सत्र के दशक में हुआ विद्या जैन हत्याकांड भी याद आता है, जिसमें देश को हिलाकर रख दिया था। इसमें विद्या के नानी डाक्टर पति ने अपनी पत्नी की हत्या, प्रेमिका के लिए कार्रवाई की। उस समय एक मशहूर पत्रिका ने इस कांड को 'राविविहाह रूप से छपा था। जिस रीति के कारण यह हत्या कायद गई थी, वह एक फीजी की पत्नी थी। जब पुलिस इस महिला और उस डाक्टर को एकदरक थाने ले आई, तो वहां एक पकड़ल रह रहा था, महिला ने गिड़गिड़ाते हुए पुलिस वालों से कहा कि यह अग्नि तो है नहीं। सजा से पहले मेरे सफ पर कर दीएंगे।

अब तक पुरुषों द्वारा ऐसे गंभीर अपराधों की लम्बी सूची बनती रही है। लेकिन अब पत्नियां भी ऐसा कर रही हैं। बहुत से विद्वान और विदुषियां कह रही हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि महिलाओं को सदैयों से दबाकर रखा गया है। अब वे ताकतवर हुई हैं, तो ऐसा कर रही हैं। आंकड़े गिनवाए जा रहे हैं कि महिलाएं तो बस छह प्रतिशत अपराध ही करती हैं। बहुसंख्य अपराध तो पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। इनकी बातें सुनकर यह कहावात याद आती है—हाजे का पन न पढी विवाह, तो क्या जानें पीर पढ़ाई। आखिर सदैयों का बदला राजा या उसी जैसे किसी निरपराध लड़के से क्यों लिया जाए।

मिर्माश की समस्या ही यह है कि अपने घरमें से बाहर उन्हें कुछ और नहीं दिखाता। वे दुनिया से असंभक्त होना का अधिकार तो मांगते हैं, मगर असंभक्तता का अधिकार किसी को नहीं देते। बस लेने की भावना का इशारा तब से संपन्न आखिर बदले वाली हो बड़ता है। ऐसे भी ज्ञान देने वाले तो ज्ञान देकर निकल लेते हैं, मगर दुनिया उनमें पड़ता है, जो इस तरह के अपराधों में जाने-अनजाने शामिल हो जाते हैं। एक लड़की ने कहा कि हम असर अपनो बांस या अधिकारियों से नाराज होते हैं, तो क्या उनकी जान ले लेते हैं। फिर यही भी कैसी नाराजगी है कि निरपराध को भुगतनी पड़े।

बस तो लोग कह रहे हैं कि सूतम के बहाने सभी रिश्तों को अपराधी नहीं कहा जा सकता। सच बता दें। ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन यदि स्त्री अपराधियों की संख्या कम है, तो मार सदैव लिए उभरे छोड़ दिया जाए। कोई सजा न मिले। जो कहा का न्याय है। अपराधी तो बाहे रहीं हो या पुरुष, उस कानून को सजा देनी ही चाहिए।

नये आपराधिक कानूनों की दिशा—दशा

—के.पी. सिंह—

तीन नये आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 को इस उम्मीद के साथ लागू किए गए थे कि भारत में ब्रिटिश काल से चली आ रही आपराधिक कानून प्रणाली नागरिकों को न्याय प्रदान करने और सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देने वाली एक जगह—केन्द्रित, प्रातिष्ठित, उद्देश्यपूर्ण एवं सक्षम संस्था के रूप में बदल जाएगी। यद्यपि किसी कानून के लागू होने के बाद एक वर्ष का समय लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इसकी सफलता या विफलता के बारे में कुछ भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है, तथापि यह समय कानून के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और अवरोधों की पहचान करने के लिए पर्याप्त संकेत प्रदान करता है।

नए कानूनों के लागू होने से पहले, कई कानून विशेषज्ञों ने उनकी उपयोगिता और व्यापकता के बारे में आशंका व्यक्त की थी। यह संशोधन में भी की जा सकती है। हालांकि यह एक कठ संकेत है कि इन धाराओं का आतंकवादियों और नौकरों के खिलाफ नान्या प्रयोग किया गया है, फलस्वरूप विदेशों में बैठकर भारत से ही उभरे बिना किसी समस्या के व्यवहार में लाया शुरू कर दिया है।

पूर देश में नए कानूनों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जा रही है और उनकी जांच की जा रही है। ऐसा केवल व्यापक पैमाने पर चलाए गए प्रशिक्षण अभियान के कारण ही संभव हो पाया है, जिसकी परिणतकताओं योजना गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, और जिसे सभी हिस्सेधारकों द्वारा उल्लासपूर्वक अपनया गया है। यहां तक कि विधि-विद्यालयों ने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में हुए इन बदलावों को बिना किसी कठिनाई के आत्मसात कर लिया है।

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को नए कानूनों में सबसे अधिक वरीयता देकर यह संकेत दिया गया है कि सरकार महिलाओं और अपराधियों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति संवेदनशील है। पुलिस ने इन प्रावधानों का बखूबी प्रयोग करने के अतिरिक्त, सजा के प्रावधानों का अपराध की संगीनता के अनुसार सखीकरण के दृष्ट-विमान को सुधारवाचक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, यद्यपि इसके परिणाम कुछ वर्षों बाद ही देखने को मिल सकेंगे।

भारत की संप्रमुता, एकाता और



अखण्डता सबसे महत्वपूर्ण है, और यह भारतीय न्याय सिद्धांत, 2023 (बीएनएस) की धारा 48 के प्रावधानों में विशेष रूप से दुर्गिगोचर होता है। इस धारा में, देश के बाहर बैठकर भारत में अपराध को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का प्राधान्य किया गया है। ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 356 के अनुसार आरोपियों की अनुपस्थिति में भी की जा सकती है। हालांकि यह एक कठ संकेत है कि इन धाराओं का आतंकवादियों और नौकरों के खिलाफ नान्या प्रयोग किया गया है, फलस्वरूप विदेशों में बैठकर भारत से ही उभरे बिना किसी समस्या के व्यवहार में लाया शुरू कर दिया है।

यही सूची और, देश की सम्प्रमुता, एकाता और अखण्डता अक्षम्य रखने के उद्देश्य से नए कानूनों में जोड़ी गई पांच 152 भारतीय न्याय संहिता के दुरुपयोग की शिकायतें निरंतर अखबारों की सुर्खियां बना रही हैं। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इन धारा का प्रयोग अभियन्ता की आजादी पर कुलघात करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय चुनावों के चर्च में है।

मुकदमों में अनुसंधान की आवश्यकता और उच्चस्तरिय बनाने के उद्देश्य से प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के प्राधान्य नए कानूनों की विशेषता है। सफ़रस्थ जब का दाया अनुसंधान प्रमाणों में बढ़ाकर जांच को निष्पक्ष और प्रभावदा बनाया गया है। परन्तु यह चिन्ता का विषय है कि अब तक डिजिटलीकरण और फास्ट्रिक प्रयोगशालाओं की स्थापित करने के प्राधान्य में नए न्याय के नए बल पाई है जितनी बचनी चाहिए थी। राज्य सरकारों के सीमित वित्तीय संसाधन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं

शुरू की हैं, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर न्यायवैधिक प्रक्रिया प्रयोगशालाओं की स्थापना और पुलिस के आयुजीकरण प्रशंशों के लिए राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है। संसधान मुद्रि और भ्रमता निर्माण के लिए इन योजनाओं का उपयोग करने का रास्चों पर निर्भर करेगा। पारम्परिक लाठीचार्ज विधियों को एक तकनीकी-गंभी पुलिस बल के रूप में बदलने के लिए पर्याप्त संख्या में साइबर-साक्षर और डिजिटल रूप से प्रशिक्षित राज-शांति की भर्ती करना, वित्तीय संपद और राजनीतिक आकाओं की अतिव्याप के कारण एक बड़ी चुनौती बन कर रह गई है। अभी तक, पुलिस विभाग कम शिक्षित ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के अवसर स्रोत हैं और भर्ती नीति में किसी भी बदलाव का जन-प्रतिनिधि ध्यान विशेष रूप से नकारा है। न्याय प्रणाली से जुड़ी अन्य संस्थाओं का भी कमोबेश यही हाल है।

आपराधिक न्याय प्रणाली के घटकों के कामकाज के आपसी सम्बन्ध के लिए आवश्यक नए नियमों और प्रोटोकॉल तय सॉफ्टवेयर को विकसित करना नए अपराधिक कानूनों की पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। यही प्रक्रिया अभी भी प्रारम्भिक अवस्था में है। यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे गृह विभाग के कामकाज के नियमों, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, पुलिस नियमों, जेल नियमों और अभियोजन एजेंसी के संकेतों के चार्टर की समीक्षा करके उसमें बदलाव करने पर ही पूरा किया जा सकता है। एकीकृत कमान के अन्तर्गत इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए सभी हिस्सेधारकों के मिल बैठकर विचार करने की आवश्यकता है। आपराधिक न्याय प्रणाली की अलग-अलग शाखाओं द्वारा पुराने नियमों को नए सारे में बदलने के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि सभी शाखाओं के सम्बन्ध में ही सखम नियम और प्रोटोकॉल निर्मित किए जा सकते हैं।

नहर में डूबा मिला किशोर का शव



1261

